वर्ष16 अंक 1 जनवरी 1994 मूल्य : दो रुपये

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

ट्रेड यूनियन केन्द्र

वर्किंग कमेटी की बैठक

गुवाहाटी, 13-15 दिसम्बर 1993

अध्यक्षीय भाषण

ों,

र्वप्रथम मैं महाराष्ट्र के भूकम्प पीड़ितों के प्रति अपनी हार्दिक ाएं एवं इस त्रासदी में हुई भारी क्षति पर दुःख व्यक्त करता हूँ। ्श में घटित यह अब तक की सबसे भयानक त्रासदी है। दो गांव तथा किल्लारी पूर्णतया नष्ट हो गए हैं। एक अनुमान के अनुसार 50,000 लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, हजारों अपंग और रात भर में हजारों बच्चे अनाथ व निराश्रय हो गए हैं। हम गों को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जो मारे गए और उनके साथ दुख करते हैं जिनके प्रिय जन उनसे बिछुड़ गए। सी आई टी यू संगठनों फंड इकट्ठा करने के लिये कदम उठाए हैं और इकट्ठी की गई राशि के मुख्य मंत्री राहत कोष में भेज़ी गई है। इस त्रासदी की ता का अनुभव करते हुए जो कुछ भी किया जा सका है, वह काफी और जिन लोगों ने अभी तक इस महान कार्य में अपना योगदान ला है, उन्हें और देरी किये बिना यह काम करना चाहिंये।

अवधि के दौरान हमारे कई नेता और कामरेड हमसे बिछुड़ चुके की स्निग्ध याद में मग्न हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते दुखी परिवारों को हार्दिक संवेदनाएं प्रेषित करते हैं।

- संकट और गहरा

रेड, भुबनेश्वर में मैने विश्व के विकसित पूंजीवादी समाजों में झानों और आर्थिक संकट का सारा भार मजदूर वर्ग के कंधों पर ने की कार्रवाईयों पर विस्तृत चर्चा की थी। यह रुझान न केवल अपितु कई मामलों में तो यह बढ़ भी रहा है।

पीय भाईचारे के देशों में बेरोजगारी की दर में 12% तक वृद्धि हैं तथा अगले वर्ष इसमें और वृद्धि होने की आशंका है। वर्तमान 70 लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं और अगले वर्ष के मध्य तक इनकी संख्या 200 लाख से भी अधिक हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों द्वारा भौगोलिक दृष्टि से लगाए गए अनुमान के अनुसार यूरोपीय भाईचारे के देशों में बेरोजगार लोगों की कुल संख्या बेलजियम, डेनमार्क और आयरलैंड की जनसंख्या के बराबर है। "ब्रिटिश इकनोमिस्ट" ने अपने 3 दिसम्बर के अंक में जर्मनी की तुलना एक डूबते जहाज के साथ की है और कहा कि जर्मनी को इन दिनों मंदे के जिस भूत का सामना करना पड़ रहा है उसकी तुलना 1930 के दशक में आए संकट के साथ की जा सकती है। जर्मन ट्रेड यूनियनें नौकरियों में कटौती के विरोध में देश व्यापी हड़ताल करने की योजना बना रही हैं। उन्हें जर्मनी की सबसे बड़ी आटो-प्रोडयूसर वोल्कसवेशन ए जी के साथ समझौता करने पर विवश होना पड़ा है ताकि कुल एक लाख की श्रम शक्ति में से 37,000 श्रमिकों की नौकरी बचाई जा सके। इसके लिये उन्हें श्रम घंटों में 36 घंटों के स्थान पर 28.8 घंटो की कमी जो चार दिनों का सप्ताह बनता है, संतोष करना पड़ा और वेतन में 10% कटौती स्वीकार करनी पड़ी। यह समझौता 1 जनवरी, 1994 से लागू होगा किन्तु कम्पनी ने फिर धमकी दी है कि वह अगले वर्ष अतिरिक्त श्रमिकों के मामले को पुनः खोलेगी।

फ्रांस में बेरोजगारी की दर सितम्बर में 12% से ऊपर हो चुकी थी। वहां बेरोजगारों की कुल संख्या 3280 लाख हो गई है। ब्रिटेन की स्थिति तो और भी खराब हो रही है। सामाजिक व्यय को अनियमित करने के नाम पर श्रम कल्याण सुविधाओं पर हमले बढ़ रहे हैं। एक और सुझाव दिया जा रहा है कि पापा तथा माँ बारी-बारी वर्ष में तीन-तीन महीने का अवैतनिक अवकाश लें। ब्रिटिंश पूंजीपतियों को चार दिन का सप्ताह करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान को भी समस्याओं का सामना कर पड़ा रहा है। हाल ही में बैंक तथा स्टाक मार्किट में आए मंदे के कारण जापानी आर्थिकता भीषण संकट में आ गई है। 60% जापानी निगम भारी स्तर पर नौकरियों में कमी

करने की योजना बना रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इन निगमों में 2350 लाख श्रमिक फालतू हैं और उनकी नौकरियां खतरे में पड़ गई हैं। अमरीका में भी अर्थनिति में कुछ सुधार होने के संकेत मिलने पर भी बेरोजगारी की सरकारी दर 6-7% पर टिकी हुई है। स्पेन के श्रमिक रोजगार में कमी लाने की सरकारी योजनाओं के विरोध में देश व्यापी आंदोलन छेड़ने की योजना बना रहे हैं। फ्रांस में एयर फ्रांस के कर्मचारियों ने सफल हड़ताल की है जो यूरोप भर के श्रमिकों के लिये एक उदाहरण बन गई है। बेलजियम में श्रमिक नौकरियों में कटौती के विरोध में संघर्षरत हैं। वहां 26 नवंबर को सफल हड़ताल की गई और देश में प्रत्येक शुक्रवार को हड़ताल होती हैं। दस दिसम्बर को देश व्यापी हड़ताल करने की योजना बनाई गई। यह वह समय था जब ब्रसेल्य में यूरोपीय भाईचारे के सम्मेलन का आतिथ्य बेलजियम कर रहा था। यह उन देशों की स्थिति है जो विश्व पूंजीवाद के ऊंची प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्र हैं।

प्रौद्योगिकी - किसके लिये ?

अमरीका में सरकारी नीतियों के विरुद्ध श्रमिकों का प्रतिरोध दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। सरकार ने नाफटा (एन ए एफ टी ए) समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जिसके अन्तर्गत वह कई उद्योगों को अमरीका से मैक्सीको स्थानांतरित कर सकती हैं। अमरीकी ट्रेड यूनियनों द्वारा इसका भारी विरोध किया जा रहा है। यद्यपि वे उस समझौते को संसद की स्वीकृति मिलने से रोक नहीं सकते। विकसित पूंजीवादी विश्व की उच्च प्रौद्योगिकी वाली आर्थिकता में ठीक ऐसी ही स्थिति बन रही है। बढ़ रहे संकट से निपटने के लिये और विकसित प्रौद्योगिकी को लागू किया जा रहा है। विचार यह है कि ऐसा करने से समस्या का निदान हो जाएगा। किन्तु इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर और कम होंगे। हम देखते है कि प्रौद्योगिकी क्रांति और पुराने उत्पादन सम्बन्धों के कारण उत्पादक शक्तियों के मध्य अंर्तदंद बढ़ती ही चली जा रही हैं। पूंजीवाद के अन्तर्गत प्रौद्योगि का उपयोग मुख्यतः मुनाफा बढ़ाने और पूंजीवादी इजारेदारी सत्ता को मजबूत बनाने के लिये ही किया जाता है। एक ओर अत्यंत शक्तिशाली उत्पादक शक्तियों तथा दूसरी ओर पुराने औद्योगिक सम्बन्धों के मध्य विरोधताईयां चल रहे संकट के प्रभाव से और तीव्र हो जाती हैं।

नयी प्रौद्योगिकी की सम्भावनाओं का पता चलने और उनकी मजबूती के कारण मनुष्य के भाग्य के बारे में नयी आशाएं उत्पन्न करने और शांति की स्थापना होने की अपेक्षा पूंजीवाद आज भी आवश्यकता से अधिक उत्पादन, बाजार के लिये भागमपेल, संरक्षणवाद का पुनः उभरना, नौकरी रहित विकास, विश्व व्यापी स्तर पर दरिद्रता, सामाजिक तनावों में वृद्धि, आपराधिक रुझानों, आतंकवाद और सर्वत्र निराशा के अंधकार जैसी व्याधियों से ग्रसित है। इसीलिये, साथियो यह बात पूर्णतया स्पष्ट है कि पूंजीवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आधुनिक प्रौद्योगिक क्रांति के लाभों का उपयोग विशाल जन समूह के जीवनस्तर को और अच्छा बनाने के लिये नहीं किया जा सकता। इसका केवल एक ही उत्तर है, पूंजीवादी व्यवस्था जो मानवता की तीव्र प्रगति के मार्ग में अवरोध खड़े करती है, के विरुद्ध संघर्ष करना। यह सर्वविदित है कि पूंजीवाद के अन्तर्गत मानव समाज प्रगति नहीं कर सकता।

नयी जागृति

मैं समयाभाव के कारण आज सभी अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर चर्चा नहीं करुंगा। केवल कुछ घटनाओं की चर्चा करूंगा जिनकी ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। रूस के राष्ट्रपति श्री येलत्सिन ने जो संविधान के अन्तर्गत निर्वाचित हुए थे, उन्हीं लोगों के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जो संविधान की रक्षा करना चाहते थे। संसद के सदस्य जो संविधान तथा कानून के शासन को बनाए रखना चाहते थे और संसद भवन (व्हाइट हाउस) के भीतर बैठे थे, को बाहर निकालने के लिये येलत्सिन केआदेश पर सेना ने उस भवन पर ही बर्बर आक्रमण कर दिया। इस संघर्ष में उनमें से कई लोग मारे गए हैं। येलत्सिन अस्थाई रूप से उन शक्तियों को पराजित करने में सफल रहा है जो रूस में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती थीं। येलत्सिन की नीतियों के विरुद्ध रूसी जनता में जागृति बढ़ रही है और रूसी जनता में उनकी शक्ति बढ़ रही है। तथाकथित येलत्सिन संविधान के अन्तर्गत हो रहे प्रस्तावित चुनावों में येलत्सिन सरकार के भाग्य का निर्णय होगा। फिर भी येलत्सिन सरकार की अमरीकी साम्राज्यवाद के आगें घुटने टेकने वाली आर्थिक एवं दूसरी नीतियों का प्रतिकार होता रहेगा। कैनेडा तथा ग्रीस में हाल ही में हुए चुनावों ने जनता ने सत्ताधारी दलों के विरुद्ध मतदान किया है क्योंकि उनकी नीतियों के फलस्वरूप वहां बेरोजगारी और गरीबी बढ़ी है। इसीलिये उन्होंने नयी सरकारों का चुनाव किया जिन्होंने लोगों को बेहतर जिंदगी देने का वादा किया है। पोलैंड में हाल ही में हुए चुनावों में पूर्व कम्युनिस्ट सत्ता में आ गए हैं। इटली में हाल ही में हुए पालिका चुनावों में भी ऐसे ही रुझान देखने को मिले हैं। पश्चिमी देशों और पूर्व सोवियत संघ की जनता धीरे-धीरे अनुभव करती जा रही है कि बुर्जुआ व्यवस्था ह्रासोन्मुखी है। उनके विरुद्ध जन संघर्ष धीरे-धीरे कई प्रकार से गति पकड़ रहा है।

एक और महत्वपूर्ण बात जिसे रेखांकित किया जाना चाहिये वह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 3 नवंबर '93 को क्यूबा सम्बन्धी प्रस्ताव को पारित करना है। यह दूसरी बार है जब संयुक्त राष्ट्र ने क्यूबा के विरुद्ध अमरीकी नाकेबंदी का विरोध किया। पिछले वर्ष 59 राष्ट्रों ने उस प्रस्ताव

का समर्थन किया था और केवल चार राष्ट्रों जिनमें अमरीका भी शामिल है, ने प्रस्ताव के विरोध में मत दिया। इस बार 88 राष्ट्रों ने प्रस्ताव के पक्ष में तथा 4 राष्ट्रों जिनमें अमरीका भी शामिल है, ने विरोध में मत दिया। सोवियत संघ के पराभव के पश्चात् अमरीकी नाकेबंदी के कारण क्यूबा को खाद्य, चिकित्सा, क्यूबाई बाजार के लिये आयात और निर्यात के क्षेत्र में भारी संकट झेलने पड़े हैं। क्यूबा को 400 लाख डालर की क्षति हुई है। इस पर भी क्यूबा अमरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है और उसे अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारे की सहानुभूति मिल रही है जबकि अमरीका अकेला पड़ता जा रहा है। क्यूबा की बहादुर जनता अमरीका के आगे कभी नहीं झुकेगी। वह अपने साहस और वीरतापूर्ण संघर्ष में हमारी ओर से सभी प्रकार की सहायता एवं समर्थन पाने के पात्र है।

कोरिया लोक गणराज्य को अपने अधीन करने के लिये अमरीका उसकी परमाणु क्षमताओं को नष्ट करने के नाम पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है जिसका कोरिया लोक गणराज्य द्वारा तीखा प्रतिकार किया जा रहा है। यहां पर भी हम अमरीकी हेंकड़ी को देखते हैं। इसकी तीव्र निंदा की जानी चाहिये।

चलते-चलते हम यहां चीन की आर्थिकता का हवाला देना चाहेंगे। पिछले कई वर्षों में वहां समानुपातिक विकास दर लगभग 12% रही। उन्होंने विदेशी पूंजीनिवेश और सहयोग के लिये कुछ क्षेत्र और विशेष औद्योगिक क्षेत्रों को खोला है। इससे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने और अपनी प्रौद्योगिकी को समय के अनुरूप विकसित करने में सहायता मिली है। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पूर्व विषम परिस्थितियां में भी हम देखते हैं कि उन्होंने भारत से तीन गुणा अधिक शक्तिशाली अपना आंतरिक ढांचा और औद्योगिक आधार विकसित किया है। उन्होंने अपने समाजवादी आधार को उसकी विशेषताओं सहित बनाए रखा है। वहां 1979 से लेकर 1993 तक 44 करोड़ डालर का विदेशी पूंजीनिवेश हुआ है। उसमें से 80% योगदान विदेशों में रहने वाले चीनियों का है।

साथियो, हाल ही की अवधि में घटित उल्लेखनीय घटना जिसे हम भूल नहीं सकते, वह ऐतिहासिक समझौता है जो 18 नवंबर को दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति डी कलार्क और अफरीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेलसन मंडेला के मध्य हुआ था। दोनों एक अंतरिम संविधान पर सहमत हो गए हैं। इसके फलस्वरूप दक्षिणी अफरीका में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार की स्थापना होगी जहां गोरों और कालों दोनों को समान मताधिकार प्राप्त होगा और अफरीका में रंगभेदी व्यवस्था का अंत हो जाएगा। सत्ता का हस्तांतरण हो जाने से अल्पसंख्यक शासन का दौर समाप्त होगा और कालों तथा गोरों के मध्य सत्ता का बटवारा होने से राष्ट्रीय एकता की प्रतीक सरकार की श्रीगणेष होगा। रंगभेद से रहित चुनाव अप्रैल 1994 में होने निश्चित हुए हैं। यह न केवल अफरीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की ही विजय हैं अपितु समूचे तौर पर यह मानवता की जीत है। दक्षिण अफरीका में लोकतंत्र के नए युग का सूर्योदय हो रहा है। हमने दक्षिणी अफरीका की जनता की इस महान विजय का हार्दिक स्वागत किया है और हर प्रकार की सफलता के लिये अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उन हजारों लोगों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा जिन्होंने रंगभेदी शासन की समाप्ति और लोकतंत्र की स्थापना के लिये अपने जीवन की आहूति दी थी।

राष्ट्रीय स्थिति

साथियों,

हमारी वर्किंग कमेटी की बैठक 4-6 जून 1993 को भुवनेश्वर में हुई थी। वहां हमने संगठनात्मक रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया था। हमने जन संगठनों के मंच के आह्वान पर भारत बंद तथा औद्योगिक हड़ताल के लिये जबरदस्त तैयारियां करने का निर्णय भी लिया था। इसे सफल बनाने के लिये बुद्धिजीवियों, छात्रों, युवाओं,महिलाओं, खेत मजदूरों, किसानों के संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने कठिन परिश्रम किया है। जन संगठनों द्वारा सांझे नारों के आधार पर इसमें शामिल होने से न केवल सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों अपितु साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ समझौते का रुख अपनाए जाने के विरोध में चल रहे संघर्ष को भी नया आयाम मिला है। इस अभियान में साम्प्रदायिकता के बढ़ने से लोकतांत्रिक आंदोलन को पहुंची क्षति और राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान केन्द्रित किया गया। बंद और हड़ताल को जनता की ओर से अभूतपूर्व प्रतियुत्तर मिला। प्रेस की रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और त्रिपुरा में बंद सम्पूर्ण जबकि तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और पंजाब लगभग सम्पूर्ण रहा। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में बंद ने अपना उल्लेखनीय प्रभाव छोड़ा। दूसरे राज्यों में भी अलग-अलग सीमा तक इसके प्रभाव को अनुभव किया गया। लगभग 2 करोड़ लोगों ने हड़ताल में भाग लिया जो भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है। मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने हड़ताल में भाग लिया और सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को जिन्होंने इस आंदोलन की सफलता के लिये दिन-रात एक करके कठिन परिश्रम किया, हार्दिक बधाई देना चाहूंगा। विपक्ष द्वारा इतनी भारी जन-कार्रवाई किये जाने पर भी केन्द्रीय सरकार ने उदारीकरण और योजनाओं का पुनर्गठन करने की नीतियां अनवरत जारी रखा हुई है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

8.5% बढ़े है। वास्तव में रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से लोगों का जीवन अत्यंत शोचनीय हो गया है। बजट घाटे में कमी करने के सरकारी दावे को अभी तक कार्यरूप नहीं दिया जा सका है और यह लगतार बढ़ता ही चला जा रहा है। जब डाक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार सम्भाला था हम पर विदेशी ऋण केवल 90,000 करोड़ रुपये था जो अब बढ़ कर 85 करोड़ डालर अर्थात् 2,65,000 करोड़ रुपये हो गया है। इस प्रकार देश पूरी तरह ऋण जाल में फंस चुका है।

इजारेदारों के शिविर में फूट

देश के बड़े उद्योगपतियों के एक वर्ग ने भी सरकार की कार्यक्षमता जबकि उस पर भारी ऋण का बोझा है, पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उसके अनुसार देश विदेशी ऋणों के जाल में फंसता चला जा रहा है।

इनमें से कई बड़े उद्योगपति जो सरकार की नयी आर्थिक नीतियों का समर्थन करते थे और कहते थे कि प्रगति का केवल यही एक मार्ग है, भी इन नीतियों की आलोचना करने लगे हैं। अब, उद्योगपतियों के प्रसिद्ध "बम्बई गुट" अर्थात देश के बड़े उद्योगपतियों ने देश में घरेलू सामान के आयात का पूर्ण उदारीकरण किये जाने पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि देश में घरेलू सामान के आयात के लिये सुविधाएं दिये जाने के फलस्वरूप स्वेदशी घरेलू सामान तैयार करने वाला उद्योग बर्बाद हो जाएगा। उनका यह भी कहना है कि वे जनरल मोटरस और आई बी एम जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जिनकी वार्षिक आय भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद से भी अधिक है। सरकार की ओर से विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ऊर्जा तथा तेल इत्यादि के क्षेत्र में डालर के रूप में 16% मुनाफे की गारंटी दिये जाने के तथ्य को रेखांकित करते हुए उन्होंने भारतीय कम्पनियों और एम एन सीज़ के मध्य करों के अन्तर को समान स्तर पर लाने की मांग ही है। सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की स्टैंडिंग कान्फ्रेंस ने भी भारतीय तथा विदेशी फर्मों के साथ समान व्यवहार करने की मांग की है। भारत सरकार से भारतीय फर्मों के साथ भी विदेशी फर्मों के समान व्यवहार करने की गारंटी मांगी जा रही है। यह अपने में ही एक अद्भुत घटना है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बढ़ना

जब से फेरा के प्रतिबंध हटा लिये गए हैं और एम एन सीज़ को भारतीय कम्पनियों में 50% से अधिक शेयर खरीदने की अनुमति प्रदान की गई ही तब से ही करने से उन्होंने उन पर अपना नियंत्रण करना शुरू कर दिया है। कई विदेशी कम्पनियों के पास तो केवल 10% से 15% तक शेयर है। निम्नलिखित तालिका से हमें पता चल जाएगा कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं:

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का भारतीय उद्यमों में बढ़ता प्रभुत्व

	से	तक	कम्पनी कहां की है
कायनेटिक हॉंडा	28.56	51	जापान
मारुति उद्योग	40	50.24	जापान
अशोक लेलैंड	39.5	51	यू.के.
डिजीटल एक्विजमैंटस	40.03	51	अमरीका
कलर चैन	40	50.52	जर्मनी
कोर्न प्रोडक्टस	40	51	यू.के.
कैडबरी इंडिया	40	51	यू. के.
ए बी बी	36.8	51	स्वीडन
अल्फा लेवल	39.92	51	स्वीडन
इंडियन शेविंग प्राडक्टस	40	51	अमरीका
पी एण्ड जी	40	65	अमरीका
इंडियन सियूइंग मशीन	40	51	अमरीका
बाटा इंडिया	40	51	कैनेडा
ए के जी एकास्टिकस	39	51	आस्ट्रिया
शेनिक एवरी	40	50	यू के
मदुरा कोट्स	40	51	यू के
सेसा गोआ	40	51	इटली
ग्लैक्सो इंडिया	40	51	यू के
नेस्टल	40	47	स्विटज़रलैंड
एल एम एल एण्ड फियागो	25.5	51	इटली
केरियर एयरकोर्न	40	51	अमरीका
पी एस आई-बुल	40	51	फ्रांस
फिलिप्स	40	51	हालैंड
ब्रुकस बांड	39.58	49.9	अमरीका
लिप्टन	40	51	यू के
पेप्सी फूडस	39:89	44.35	अमरीका
इंडियन आक्सीजन	39.76	51	यू के
एस आर एफ - नियोडैंसो	26	40	जापान

सार्वजनिक क्षेत्र कतलगाहों में धकेला गया

इसलिये विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इन फर्मों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। ऊर्जा के साथ-साथ कोयला क्षेत्र में भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारी सुविधाएं देकर आमंत्रित किया जा रहा है। तेल क्षेत्र में भी जहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बिस्तर गोल कर दिया गया था और राष्ट्रीयकरण होने पर उन्हें देश से बाहर खदेड़ा गया था, बड़ी शान के साथ उन्हें पुनः वापस लाया जा रहा है। कालटैक्स, मेबल, शैल, ओमान आयल तथा अन्य बड़ी कम्पनियां पुनः भारत आ रही हैं। देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की फार्मास्यूटिकल कम्पनी इंडियन ड्रगस एण्ड फार्मास्यूटिकलस लिमिटिड (आई डी पी एल) भी अपने परिसमापन की प्रतीक्षा कर रही है। अत्यंत कुख्यात बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उस पर नियंत्रण करके भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की खुली छूट दे दी जाएगी और जीवन रक्षक दवाईयां हमारे देश के

बहुसंख्यक लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएंगी। मैं यहां इसके कुप्रभावों की चर्चा करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। यदि बिजली (ऊर्जा) और तेल महंगे हो गए और इन क्षेत्रों का नियंत्रण बहुराष्ट्रीय हितों के पास चला जाएगा तो यह हमारे राष्ट्र की प्रगति और सम्प्रभुता के लिये खतरनाक होगा। इसका तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता।

सार्वजनिक क्षेत्र में अस्थिरता लाने और उसका निजीकरण करने सम्बन्धी विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निदेशों को कार्यरूप देने के भारत सरकार के उन्मत्त प्रयासों की चर्चा मैं यहां पर नहीं करूँगा। हमारे महासचिव द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। फिर भी, मैं कृषि इन नीतियों के खतरनाक दुष्परिणामों की और आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। बजट और वित्तीय घाटे में कमी लाने के नाम पर उर्वरक, पानी और विद्युत की सबसिडी में भारी कटौती की जा रही है और इन के मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि होने जा रही है। राज्य सरकारों को विद्युत और पानी के मूल्यों में उनकी वास्तविक लागत के आधार पर वृद्धि करने के निदेश दिये गए हैं। उर्वरक उद्योग जो इस समय अस्थिर स्थिति में है, बंद होने के कागार पर खड़ा है। इससे इस क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का पदार्पण होगा और वे उर्वरक के मूल्यों में इतनी अधिक वृद्धि कर देंगी। हमारे किसानों की बहुसंख्या के लिये असहनीय होंगे। इससे न केवल हमारे किसान भारी संख्या में बर्बाद हो जाएंगे अपितु इसका कृषि उत्पादन जिसमें खाद्य सामग्री भी शामिल है, पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम अपनी खुराक सम्बन्धी आवश्कताओं के लिये आयात पर निर्भर करने लगेंगे।

साथियो, इसलिये हमें अपने संघर्ष को तेज करने और बड़ी तथा सख्त कार्रवाईयां करने के लिये समूचे ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ ही जनता के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले जन संगठनों को लामबंद करने हेतु दुगने प्रयास करने होंगे।

साम्प्रदायिक शक्तियों को करारा जवाब

हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, दिल्ली तथा मिजोरम विधान सभाओं के हाल ही में सम्पन्न हुए चुनावों में जनता ने भारतीय जनता पार्टी की खतरनाक चालों और साम्प्रदायिक राजनीति का करारा जवाब दिया है। उन्होंने इस दावे के साथ चुनाव लड़ा था कि वे सारे राज्यों में सत्ता प्राप्त कर रहे हैं और यह केन्द्र में राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिये उनका शुभारम्भ होगा। उत्तर प्रदेश में जहां उन्होंने मन्दिर के प्रश्न पर चुनाव लड़ा था, राजनीतिक दृष्टि से जागरूक मतदाताओं ने उनके स्वप्न को भंग करके रख दिया है। जनता ने उनके दावे को अस्वीकार करके उन्हें सत्ता से वंचित कर दिया है। राजस्थान में भी जहां उनके सदस्यों की संख्या कम हुई है, वे दल-बदल कराने के पश्चात् ही सत्ता में आ सके हैं। दूसरे दो राज्यों मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में भी उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है। केवल नवगठित राज्य दिल्ली में ही उन्हें श्रीमती इंदिरा गांधी की नृशंस हत्या के पश्चात् हुए दंगों में कांग्रेस-इ के अक्षम्य अपराधों के कारण बहुमत प्राप्त हो सका है। अतः इन राज्यों की जनता ने देश के धर्मनिर्पेक्ष आधार और एकता को बनाए रखने के पक्ष में अपना मत दिया हैं। दूसरे, भाजपा को कम करके आंका नहीं जाना चाहिये। तीसरे, सामाजिक असमानता का लाभ उठा कर जातिवादी तत्व उभर कर सामने आ गए हैं जो जनता को जाति और समुदाय के नाम पर विभाजित कर रहे हैं। सामाजिक समस्याएं अत्यंत गंभीर हैं और प्रगतिशील राजनीतिक दलों एवं संगठनों को इस ओर ध्यान देना चाहिये। सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को दूसरे वर्गों के साथ मुख्यधार में लाया जाए। उन्हें केवल जातिवादी दलों की दया पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिये। ऐसा प्रभावशाली ढंग से तभी किया जा सकता है जब इन वर्गों को आर्थिक मांगों पर संघर्ष करने के लिये लामबंद किया जाए और इन्हें खेत मजदूरों के लिये अच्छे वेतन एवं सुविधाओं के साथ-साथ तीखे भूमि-सुधारों के लिये संघर्ष में शामिल किया जाए। जनता के इन वर्गों को सामूहिक जन कार्रवाईयों में शामिल करने के लिये ट्रेड यूनियनों को पहल करनी चाहिये।

संयुक्त कार्रवाईयों में वृद्धि

सरकारी हमलों के विरोध में मजदूर वर्ग के संयुक्त आंदोलन के विस्तार की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये। कई उद्योगों तथा कारखानों में अखिल भारतीय स्तर की हड़तालों के अतिरिक्त सरकार तथा मालिकों के विभिन्न हमलों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिये मजदूर एक हो रहे हैं। सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा 7 सितम्बर की अखिल भारतीय इस्पात हड़ताल में दिखाई गई एकता उल्लेखनीय है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने भी वेतन मानों में संशोधन तथा दूसरे मुद्दों को लेकर विभिन्न ट्रेड यूनियनों में एकता लाने के आधार पर संघर्ष किया गया था। यद्यपि उनकी उपलब्धि उल्लेखनीय नहीं है तथापि इससे वेतन जाम करने की सरकार द्वारा प्रचारित नीति को करारा जवाब दिया जा सका है। तमिलनाडु परिवहन कर्मचारियों तथा केरल रोड ट्रांस्पोर्ट वरकर्स द्वारा किये गए संयुक्त संघर्ष इसके दूसरे उदाहरण हैं। केरल राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी अपनी मांगों के लिये संयुक्त संघर्ष करके तालाबंदी तथा औद्योगिक बीमारी के प्रश्न पर सरकार से कई सुविधाएं प्राप्त की हैं।

उद्योग के सभी क्षेत्रों में श्रमिकों द्वारा अनूठी एकता का प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे नयी घटना एच एम टी कर्मचारियों द्वारा एच एम टी बचाओ समिति जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं, का गठन किया जाना है। एफ ए सी टी और कोचीन शिपयार्ड में भी यही बात दोहराई गई। वहां सभी ट्रेड यूनियनें तथा अधिकारियों के संगठन अपना रोजगार और उद्योग की रक्षार्थ एकजुट हो गए। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योगों में श्रमिक, कर्मचारी तथा अधिकारी यद्यपि उनके अलग-अलग संगठन हैं, अपने ऊपर हो रहे हमलों का सामना करने के लिये एकजुट हो रहे हैं। एन टी सी मिलों में बीमार इकाईयों के पुनरुजीवन के प्रश्न पर संयुक्त दृष्टिकोण अपनाकर संयुक्त स्टैंड लेने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। सरकार ने एन टी सी मिलों के 1,35,000 श्रमिकों में से 90,000 श्रमिकों का रोजगार छीनने का अपना इरादा घोषित किया है। फिर भी, इस क्षेत्र की ओर हमें ध्यान देने की आवश्कता है। यह स्वाभाविक ही है कि विपत्ति आने पर उससे प्रभावित होने वाले एकजुट हों और उसका सामना करें। इसके साथ ही सरकार की वर्ग-नीतियों के प्रकट होने से ट्रेड यूनियन एकता में एक नया तत्व उभर कर सामने आ रहा है और जो लोग पहले उन नीतियों का समर्थन करते थे, खुल कर उसके विरोध में सामने आ रहे हैं। ऐसे कई संयुक्त आंदोलनों में सी.आई.टी.यू. मजदूरों के हितों की खातिर समूचे मजदूर वर्ग को लामबंद करने के लिये प्रमुख भूमिका निभा रही है। सी आई टी यू को मजदूर वर्ग को संगठन के साथ जोड़ने के लिये समुचित कदम उठाने चाहियें। यही स्थिति की मांग है। सी आई टी यू द्वारा पारित संगठनात्मक रिपोर्ट में उचित रूप से इस बात पर बल दिया गया है और ट्रेड यूनियनों की कनफेडरेशन बनाने हेतु सभी ट्रेड यूनियनों के साथ सम्पर्क करने का निर्णय किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों में इस बात का विशेष महत्व है। अत: सी आई टी यू ने गम्भीरता से कारखाना स्तर, उद्योग स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर एकता को विशाल एवं मजबूत करने का निर्णय किया है। हमारा कर्तव्य है कि हम ट्रेड यूनियन एकता तथा सम्बद्धता को मजबूत बनाए और विश्व बैंक के निर्देशों पर सरकार और मालिकों द्वारा किये जा रहे हमलों का मुंहतोड़ उत्तर दें।

जैसा कि हम जानते हैं भारत सरकार की नीतियां विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारी आर्थिकता पर आधिपत्य जमाने की अनुमति देकर आर्थिक स्वतंत्रता का समर्पण करने की है। ऐसी स्थिति में विशाल वर्ग सरकार के साथ टकराव की मुद्रा में आ गए हैं। इसलिये विशाल एकता की सम्भावनाएं बढ़ रही हैं। इन क्षेत्रों में सी आई टी यू को सक्रिय हस्तक्षेप करके लोगों की एकता को विशाल एवं सुदृढ़ बनाना चाहिये।

हमारी संगठनात्मक रिपोर्ट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के मामलों के महत्व पर बल दिया गया है और इस सम्बन्ध में पहले ही हमने कुछ कदम उठाए हैं। तथापि जबसे बड़ी कम्पनियों को इस क्षेत्र में दाखिल होने की अनुमति देने की नीतियां लागू हुई हैं तभी से ही लघु उद्योगों को अपना कारोबार जारी रखने में कठिनाईयों का अनुभव हो रहा है; तालाबंदी एवं लाकआउट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है; इसके विरोध में हमें समुचित कदम उठाने चाहियें। हाल ही में अखिल भारतीय बीड़ी सम्मेलन हुआ। उसमें बीड़ी मजदूरों जिनकी संख्या देश भर में 60 लाख से अधिक है, के कष्टों एवं कठिनाईयों पर प्रकाश डाला गया है। उनमें बहुसंख्या महिलाओं की है। उन्हें निर्धारित न्यूनतम वेतन तक नहीं दिये जाते और कई राज्यों में तो समुचित न्यूनतम वेतन तक घोषित नहीं किये गए हैं। वे भारत में असंगठित मजदूरों की कुल संख्या का 11% हैं। साथियो, इसलिये सी आई टी यू की राज्य समितियों को समुचित कदम उठा कर इस वर्ग को संगठन में लाना चाहिये। बीड़ी मजदूरों की नवगठित अखिल भारतीय समिति ने एक कार्रवाई योजना तैयार की है। हमारे साथियों को उसे गम्भीरता से लेना चाहिये।

सरकारी हमलों का मुंहतोड़ उत्तर देने हेतु कार्रवाई योजना बनाने के लिये बीमार उद्योगों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया है। इसे तुरंत कार्यरूप देना चाहिये। साथीयों, हम 8-12 मार्च'94 पटना में अपना आठवां सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमें जहां सम्मेलन को सफल बनाने के लिये काम करना होगा, वहीं मजदूर वर्ग और देश की जनता के विरुद्ध किये जा रहे हमलों को परास्त करने के लिये सुदृढ़ एवं शक्तिशाली कार्रवाईयां करनी होंगी। इसके लिये हमें सभी कदम उठाने होंगे।

संपादक मंडल

एम. के. पंधे (चेयरमैन)

पी. के. गांगुली (कार्यकारी सम्पादक)

नीरेन घोष,

एम. एम. लारेंस,

विमल रणदिवे,

रंजीत बसु

सीटू वर्किंग कमेटी की गुवाहटी बैठक

मौजूदा आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्ष और तेज करने का संकल्प

☐ पी. के. गांगुली

गुवाहाटी में 13 से 15 दिसंबर तक आयोजित सीटू की वर्किंग कमेटी की बैठक ने गाट समझौते को संपन्न करने के लिए डंकल मसौदे पर हस्ताक्षर करने के नरसिंह राव सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की है। सरकार की आर्थिक नीतियों से संबंधित प्रस्ताव में और ट्रेड यूनियन आंदोलन पर फौरी कामों से संबंधित प्रस्ताव में वर्किंग कमेटी ने देश में निरंतर बिगड़ती जा रही स्थिति और आइ एम एफ के दबावों के प्रति बढ़ते जन प्रतिरोध के प्रति सरकार की पूर्ण संवेदनहीनता के प्रति और इन नीतियों को लागू करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते जाने जिसकी परिणति प्रतिगामी डंकल प्रस्तावों को स्वीकार करने में हुयी है : के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने सरकार के दब्बू रुख की कड़ी निंदा की और इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने तथा इन्हें मात देने के लिए संघर्ष करने की खातिर जनता को लामबंद करने के लिए देशव्यापी आंदोलन चलाने के कार्यक्रम बनाने का आह्वान किया। बैठक ने दोहराया कि डंकल प्रस्ताव न तो विदेशी इक्विटी के मामले में और न निवेश के मामले में ही किसी तरह के प्रतिबंधों के हामी हैं। इन प्रस्तावों की मांग है कि किसी तरह की लाइसेंस प्रणाली न हो। आयात पर किसी तरह का प्रतिबंध न हो और सबसे बड़ी बात यह कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश और उनके कामकाज पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून या नीतियां उन्हें नहीं चाहिए और वे ये भी चाहते है कि उन्हें भी भारतीय क्षेत्र के समान ही दर्जा मिले। बैठक का मानना था कि हालांकि डंकल मसौदे के तीन पक्ष हैं : व्यापार संबंधी निवेश उपाय (ट्रिम्स), व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) और व्यापार तथा सेवाओं संबंधी आम समझौता (गाट्स) लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पूर्ण नियंत्रण और एक नये साम्राज्यवादी निजाम का रास्ता तैयार करने में सक्षम हैं। ट्रिप्स में नव-औपनिवेशिक शोषण के सबसे घृणित रूप शमिल हैं। इसके जरिये वे पेटेंट कानून समेत हमारे बौद्धिक संपदा अधिकारों को संशोधित करवाना चाहते हैं और पेटेंट संबंधी 1883 की पैरिस कन्वेंशन का सदस्य बनने पर मजबूर करके भारत को गुलामी के दिनों की ओर वापस ले जा रहे हैं। इस प्रक्रिया का परिणाम आत्मनिर्भरता की पूर्ण समाप्ति और औद्योगिकरण का पूर्ण खात्मा होगा और इस तरह सेवा और वित्तीय क्षेत्रों समेत कृषि और उद्योग दोनों को ही बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपा जा रहा होगा। बैठक ने सभी ट्रेड यूनियनों तथा जनसंगठनों, चाहे उनकी संबद्धता कुछ भी क्यों न हो, से अपील की कि राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए एकजुट होकर कार्रवाइयों को और तेज करें।

सीटू अध्यक्ष ई बालानंदन द्वारा झंडा फहराये जाने और शहीद वेदी पर माल्यार्पण किए जाने के साथ बैठक शुरू हुयी। स्वागत समिति के चेयरमैन साशाकमाल हांडीक ने बैठक में उपस्थित लोगों का स्वागत किया। का. अचिंत्य भट्टाचार्य तथा इस अवधि में चल बसे अन्य नेताओं की स्मृति में शोक प्रस्ताव पारित किया गया। महाराष्ट्र के भूकंप में मारे गए लोगों और शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

महासचिव की रिपोर्ट

एम के पंधे ने महासचिव की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार ने एक के बाद एक आई एम एफ तथा विश्व बैंक की सारी शर्तें स्वीकार की ली हैं और डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए जाने में यह प्रक्रिया अपने उत्कर्ष पर पहुंची है जो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए वास्तविक खतरा है। आर्थिक सुधारों की इस अवधि में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र में गतिरोध बना रहा है। जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में उत्पादन में वास्तव में गिरावट आयी है। औद्योगिक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उपभोग में कमी आयी है जो देश की जनता में गरीबी के बढ़ते स्तर की सूचक है। निर्यातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि डालर के हिसाब से देखा जाये तो वास्तव में इसमें गिरावट आयी है। 1990-91 में निर्यात 18.1 करोड़ डालर के हुए जबकि 1991-92 में यह घटकर 17.9 करोड़ के बराबर रह गए। रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पूंजीवादी देशों की लूट में बढ़ोतरी हुयी है। क्योंकि पूंजीवादी देशों की लूट में बढ़ोतरी हुयी है। क्योंकि पूंजीवादी देशों को बाजार की भारी जरुरत है इसलिए वे भारत पर अपना माल थोप रहे हैं। और सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर रही है। उन्होंने निजी क्षेत्र में बढ़ती बीमारी का भी जिक्र किया और कहा कि निजी क्षेत्र की बीमार इकाईयों की तादाद चार लाख सत्तर हजार तक पहुंच चुकी है लेकिन आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के दवाब में ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे औद्योगिक बीमारी सार्वजनिक क्षेत्र की ही खासियत हो। उन्होंने कहा कि बाजार की अर्थव्यवस्था का तर्क हमेशा लघु तथा परंपरागत उद्योगों की कीमत पर इजारेदार घरानों को मजबूत करता है। कारखाना बंदी तथा औद्योगिक बीमारी के चलते बेरोजगारी की स्थिति भी गंभीर होती जा रही हैं।

आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के दबाव में सरकार अब श्रम कानूनों को भी बदलना चाहती है ताकि नयी आर्थिक नीतियों का विरोध कर रहे संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन पर रोक लगायी जा सके। उन्होंने एकजुट संघर्षों की सराहना की जिसमें इंटक तथा बी एम एस भी शामिल हुयी।

उन्होंने बी आई एफ आर की भूमिका की भी कड़ी आलोचना की। उसके हवाले की जाने वाली सार्वजनिक इकाइयों का अर्थ है उनका समाप्त होना या उनकी निजी हाथों में सौंपा जाना और सरकार ने उसे यह अधिकार आइ एम एफ तथा विश्व बैंक के दबाव में आकर ही दिया है। गोस्वामी कमेटी भी विश्व बैंक की इन्हीं सिफारिशों के सुर में अपना सुर मिलाती है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाइयों को जल्द से जल्द बंद किया जाये। उन्होंने निर्गम नीति और तथाकथित राष्ट्रीय पुनर्वास फंड की निंदा की जिसके लिए विश्व बैंक ने 50 करोड़ डालर दिए हैं ताकि औद्योगिक बंदी की नीति को लागू किया जा सके।

उन्होंने 19 अगस्त के जेल भरो आंदोलन तथा 9 सितंबर के भारत बंद की समीक्षा करते हुए जनता के विभिन्न तबकों के बीच बढ़ती एकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जनसंगठनों के बीच बढ़ती एकता सांप्रदायिक ताकतों के लिए चुनौती बनकर सामने आ रही है। उन्होंने सांप्रदायिक ताकतों की कड़ी निंदाकी जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को तार-तार का देना चाहती हैं। रिपोर्ट में देश की एकता तथा अखंडता और आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए इन दोनों खतरों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया गया था।

रिपोर्ट में 22 सूत्री मांग पत्र को लेकर सीटू के नेतृत्व में 14 जुलाई को हुयी असंगठित मजदूरों को देशव्यापी हड़ताल का जिक्र करते हुए असंगठित मजदूरों की लामबंदी को और बढ़ाने का आह्वान किया गया था।

हाल के संघर्षों के दौरान ट्रेड यूनियन एकता के अनुभवों के बारे में विस्तार से बताते हुए आह्वान किया था कि इस एकता को और मजबूत किया जाना चाहिए ताकि कन्फेडरेशन के गठन का सीटू का लक्ष्य पूरा हो सके। उन्होंने कामगार महिलाओं के बीच कामकाज में और सुधार करने, सीटू द्वारा तैयार की गयी सांगठनिक रिपोर्ट के विभिन्न पहलुओं को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सीटू के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी जिक्र किया। अंत में उन्होंने मजदूर वर्ग तथा दूसरे जन संगठनों के एकजुट संघर्ष को और विकसित करने का आह्वान किया। जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में जन संघर्षों को और तीव्र करने का भी उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने 3 से 7 मार्च तक पटना में होने जा रहे और सीटू के आठवें सम्मेलन के बारे में भी बताया और इसे शानदार रूप से सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया।

रिपोर्ट पर बहस

रिपोर्ट पर हुयी बहस में 26 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने 19 अगस्त को जेल भरो आंदोलन,9 सितंबर के भारत बंद,ट्रेड यूनियन एकता, दूसरे जनसंगठनों के साथ सहयोग, नयी आर्थिक तथा औद्योगिक नीति को लागू किए जाने के चलते संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन पर बढ़ते हमलों आदि के अपने अनुभवों के बारे में बताया। अनेक प्रतिनिधियों का कहना था कि निजी क्षेत्र में औद्योगिक बीमारी पर सीटू तथा ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति का एक कन्वेंशन का आयोजन करना चाहिए। नयी आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा पर भी समान जोर दिया जाना चाहिए और सरकार के कुप्रचार का मुकाबला करना चाहिए। डंकल प्रस्तावों के खिलाफ भी संघर्ष तेज करने की जरूरत पर बल दिया गया। प्रतिनिधियों ने नयी आर्थिक नीति के साथ ही साथ सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष की उतनी ही जरूरत बतायी क्योंकि संघ परिवार के नेतृत्व में ये सांप्रदायिक ताकतें देश की एकता तथा अखंडता को तोड़ने का भी काम कर रही हैं।

देशव्यापी जत्थे तथा संसद मार्च का सुझाव

जनता के विभिन्न हिस्सों को नयी आर्थिक नीति तथा डंकल मसौदे के खिलाफ लामबंद करने की जरूरत पर जोर देते हुए प्रतिनिधियों ने किसानों, खेतमजदूरों को लामबंद करने के लिये देशव्यापी जत्थों का आयोजन करने का सुझाव दिया। उनका सुझाव था कि ये जत्थे जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किए जायें। ये जत्थे गांव से कस्बों,जिले से शहरों,शहरों से राज्य की राजधानियों और राज्य की राजधानियों और राज्य की राजधानियों तथा देश के विभिन्न केंद्रों से दिल्ली तक आयोजित किए जायें और दिल्ली में संसद के सामने विराट रैली में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। बैठक ने हरियाणा के कर्मचारियों के संघर्ष, डाक कर्मचारियों की हड़ताल, कामगार महिलओं को मातृत्व लाभ, दक्षिण अफ्रीका, त्रिपुरा में वाममोर्चे की जीत, प्रस्तावित नये औद्योगिक संबंध विधेयक, नयी आर्थिक नीति और ट्रेड यूनियन आंदोलन के फौरी कामों पर प्रस्ताव पास किए।

एम के पंधे ने बहस का जवाब दिया और प्रतिनिधियों के अनेक सुझावों को स्वीकार कर लिया। उन्होंने जत्थों तथा संसद मार्च के सुझाव का स्वागत किया और जनसंगठनों के राष्ट्रीय मंच के सामने इस सुझाव को रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने सीटू द्वारा तय किए कामों को पूरा करने का आह्वान किया। इसके बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकृत हुयी। बालानंदन ने अंत में देशव्यापी कार्रवाई की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया और सीटू की असम राज्य कमेटी तथा वालंटियरों को धन्यवाद दिया।

बाद में जजेज मैदान में आम सभा हुयी जिसमें करीब दस हजार मजदूरों ने भाग लिया। विधायक साशा कमाल हांडीक ने सभा की अध्यक्षता की। सभा को बालानंदन, एल के पंधे, विमल रणदिवे, अमल घोष दस्तीदार, सुभाष चक्रवर्ती, सांसद उद्धव बर्मन और नदेश्वर ताल्लुकदार ने संबोधित किया।

सी आई टी यू वर्किंग कमेटी की गुवाहाटी बैठक

आर्थिक नीतियों के विरुद्ध तथा आंदोलन के नए चरण सम्बन्धी प्रस्ताव

सी आई टी यू वर्किंग कमेटी की गत 13-15 दिसम्बर 1994 को गुवाहाटी में बैठक हुई। इस बैठक में डंकल प्रस्ताव में कोई संशोधन किये बिना ही उस पर हस्ताक्षर करने के भारत सरकार के निर्णय पर चिंता व्यक्त की गई। यह बात कम खेद जनक नहीं है कि भारत सरकार ने ट्रेड यूनियनों एवं समस्त जन संगठनों तथा सभी देश भक्त एवं लोकतांत्रिक वर्गों के भारी विरोध को अनदेखा करके इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये हैं। उसने वाणिज्य मंत्रालय की स्टैंडिंग संसदीय समिति द्वारा दी गई उस चेतावनी की भी परवाह नहीं की है जो उसने एक नोट भेज कर दी थी।

डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना उस प्रक्रिया की चरम परिणिति है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निदेशित नयी आर्थिक नीति तैयार करने के साथ शुरू हुई थी। इस प्रकार सरकार ने साम्राज्यवाद एजेंसियों के समक्ष देश की आर्थिक सम्प्रभुता का समर्पण कर दिया है।

भारत सरकार का यह वक्तव्य कि गाट की उरुगुवे दौर की वार्ता के पश्चात् जारी डंकल प्रस्ताव में सुझाई गई मुक्त व्यापार व्यवस्था से भारत को लाभ पहुंचेगा, कोरी कल्पना और पूर्णतया निराधार है। बताया गया है कि इससे हमारी औद्योगिक रूप से विकसित देशों के बाजार तक पहुंच हो जाएगी किन्तु वास्तव में इस वाहन का प्रयोग गाट में शामिल विकसित पूंजीवादी देश ही करेंगे। इसके द्वारा तृतीय विश्व के देशों को ब्लैक मेल किया जाएगा और एक साम्राज्यवादी सत्ता द्वारा बढ़ रहे असमान व्यापार के माध्यम से शोषण के नव उपनिवेशवादी फंदे में जाने के लिये विवश किया जाएगा। उन्हें साम्राज्यवादी देशों के बौद्धिक सम्पदा कानून मानने और अपने यहां विदेशी पूंजी के निवेश एवं कारोबार के मार्ग में आने वाली बाधाओं जिनमें देश के कानूनों को समाप्त करना या उनमें संशोधन करना भी शामिल है, को दूर करने के लिये कहा जाएगा ताकि वे बहुराष्ट्रीय निगमों के आगे अपनी सम्प्रभुता कर समर्पण कर सकें।

विश्व व्यापी विशेष रूप से तृतीय विश्व के देशों के अनुभव हमें बताते हैं कि मुक्त व्यापार से गरीबी को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसके विपरीत उसमें वृद्धि ही होती है। वास्तविक पीड़ित तो सामान्य जन मजदूर तथा किसान ही होते हैं। इसलिये यूरोप तथा दूसरे देशों में मजदूरों तथा किसानों द्वारा डंकल प्रस्ताव के विरोध में भारी प्रदर्शन किये गए। अमरीका, कैनेडा और मैकसीको में मजदूरों ने एक और मुक्त व्यापार समझौते एन ए एफ टी ए (नाफटा) जिसका शिकार अंतत मैक्सीको ही होगा, के विरोध में प्रत्यक्ष आंदोलनात्मक कार्रवाईयां की हैं।

जहां तक डंकल प्रस्ताव का सम्बन्ध है, उसकी तीन रणनीतियां हैं। ये हैं व्यापार से सम्बन्धित निवेशिक कदम (ट्रिम्स), व्यापार से सम्बन्धित बौद्धिक सम्पदा अधिकार ट्रिप्स तथा व्यापार एवं सेवाओं पर आम समझौता (गाट) इत्यादि। ये अन्तर सम्बन्धित हैं और भारतीय अर्थतंत्र जिसमें कृषि वित्त और सेवा के क्षेत्र भी शामिल हैं पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिये बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सहायता देती है। केवल ट्रिप्स को ही नव-उपनिवेशवादी शोषण का भयंकर स्वरूप कहा जा सकता है। वे भारतीय बौद्धिक सम्पदा अधिकारों जिनमें इंडियन पेटैंट लाज़ भी शामिल है, में मूलभूत संशोधन करके भारत को उसी स्थिति की ओर ले जाना चाहते हैं जहां वह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय था और 1883 के पेटैंटस पर आयोजित पेरिस सम्मेलन की पार्टी भारत को बनाना चाहते हैं। इसका परिणाम देश के पूर्ण गैर स्वदेशीकरण और गैर उद्योगीकरण की प्रक्रिया में निकलेगा। इससे जीवन रक्षक दवाईयों के मूल्यों में 200 से 300 गुणा तक वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगमों का हमारे कृषि उत्पादों पर पूर्ण नियंत्रण होगा, इसलिए उससे जन वितरण प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होगी और सभी आवश्यक जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाएगी।

आर्थिक सुधारों के लगभग तीन वर्षों की अवधि के मध्य सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। इससे जनता के सभी वर्गों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए अकथनीय कष्ट और कठिनाईयां अपना फन फैला कर खड़ी हो गई हैं। तालाबंदी की घटनाएं और औद्योगिक बीमारी बढ़ चुकी है। इस अवधि में विशेष रूप से निजी क्षेत्र की लगभग 3 लाख से लेकर 4-7 लाख तक इकाईयां बंद हो चुकी हैं। हजारों-लाखों मजदूरों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है। बड़ी द्रुत गति से सार्वजनिक क्षेत्र को तोड़ा और उसका निजीकरण किया जा रहा है। लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों को बहुत ही कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की 98 इकाईयों पर बी आई एफ आर की मार पड़ने जा रही हैं। विश्व बैंक के दबाव में आकर बी आई एफ आर को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमार इकाईयों को बंद करने के अधिकार दिये जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को कार्यरूप देना शुरू किया जा चुका है। इसका दुष्प्रभाव लगभग 10 लाख श्रमिकों पर पड़ेगा।

एस आई सी ए में और संशोधन किया जा रहा है ताकि बी आई एफ आर गोस्वामी समिति की संस्तुतियों के आधार पर तेजी के साथ बीमार इकाईयों बंद करने की मशीनरी बन सके। इसी प्रकार बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र व बीमा क्षेत्र में भी बहुराष्ट्रीय निगामों का प्रवेश सुगम बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि इस राष्ट्रीय अर्थतंत्र के इस विशेष क्षेत्र पर उनका आधिपत्य स्थापित हो सके।

भारत सरकार ने हाल ही में पांच निजी ऊर्जा परियोजनाओं को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। ये जन हित के महत्वूपर्ण मामले हैं। ये पहली निजी ऊर्जा परियोजनाएं हैं जिनकी स्वीकृति नयी आर्थिक नीति के ढांचे के अन्तर्गत दी गई। इसके साथ ही उन्हें 16 प्रतिशत लाभांश की निश्चित वापसी और निर्यात रुपांतरण के सभी जोखिम दूर करने का आश्वासन दिया गया है। उक्त स्वीकृति का विशेष मुद्दा वह मूल्य है जिसका भुगतान राज्य बिजली बोर्डों द्वारा ऊर्जा कम्पनियों को किया जाएगा। इससे निश्चित होने वाले मूल्यों पर उपभोक्ताओं के भिन्न-भिन्न वर्गों को बिजली की आपूर्ति होगी। आर्थिकता के विभिन्न क्षेत्रों को किफायती मूल्यों पर बिजली दी जाएगी। इससे बिजली के मूल्यों में भारी वृद्धि होगी। यही नहीं राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार द्वारा छोटे गए घाटों का बोझ भी जनता पर डाला जा सकेगी। स्वदेशी तथा विदेशी निजी निवेशकों के लिये गारंटियों और शर्तों का लाभ एन टी सी सी और राज्य बिजली बोर्डों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों को नहीं दिया जा रहा। यही नहीं विदेशी ऊर्जा कम्पनियों को तो केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्प्रभुता की गारंटी भी दी जा रही है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि राज्य बिजली बोर्ड निजी ऊर्जा कम्पनियों को उनकी राशि का भुगतान नहीं कर सकेंगे तो उस स्थिति में केन्द्रीय सरकार संचित कोष या जैसे भी वे चाहें इस राशि का भुगतान उन्हें कर देगी। केन्द्रीय सरकार यह राशि उस के द्वारा राज्यों को प्रदत्त योजना सहायता में से काट लेगी। इसके परिणामस्वरूप राज्यों के पास सामाजिक और आर्थिक खर्चे के लिये उपलब्ध कुल आर्थिक संसाधनों में भारी कमी हो जाएगी। एक बार यदि ऊर्जा क्षेत्र के लिये इस प्रकार की योजना को स्वीकृति मिल गई तो आंतरिक पूंजीनिवेश के दूसरे क्षेत्र में भी ऐसी योजनाएं लागू करने के लिये निश्चित रुप से अबाव बढ़ जाएगा।

लघु उद्योग क्षेत्र, परम्परागत उद्योगों और संगठित क्षेत्रों में इजारेदारों द्वारा घुसपैठ किये जाने के फलस्वरूप इन क्षेत्रों की स्थिति भी इस अवधि में खराब हुई है। बैठक में असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के श्रमिकों को बधाई दी गई जिन्होंने 14 जुलाई '93 को पहली बार देश व्यापी हड़ताल की और आर्थिक नीतियों के विरोध में आयोजित भारत बंद में भाग लिया। जबकि नयी आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत नकारात्मक व्यापार संतुलन के माध्यम से देश पर पहले ही आर्थिक बोझ डाला जा चुका है उस पर गाट समझौता व्यापार असंतुलन को और चौड़ा कर देगा। सरकार के लम्बे चौड़े दावों के बावजूद इस अवधि के दौरान विदेश ऋण 90,000 करोड़ रुपये से बढ़ कर 2,65,000 करोड़ रुपये हो गया है। 1992-93 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति विदेश ऋण 82 डालर (लगभग 2,624/-रुपये)था। इस अवधि में बेराजगार लोगों की संख्या 340 लाख से बढ़ कर 380 लाख हो गई है।

सभी क्षेत्रों में देश की स्थिति बिगड़ती जाने पर भी सरकार वास्तविकताओं की ओर से पूर्णतया आंखें मूंद रही है। वह अभी तक इन नीतियों के प्रति बढ़ रहे विरोध को भी समझ नहीं पर रही है जिसकी अभिव्यक्ति दो देशव्यापी हड़तालों, बोट क्लब पर भारी जनसभा और 9 सितम्बर के भारत बंद के रूप में हो चुकी है। इसके विपरीत वह मुद्रा कोष की प्रत्यक्ष देखरेख में इन नीतियों को कार्यरूप देने पर अड़ी हुई है।

बैठक में मजदूरों और ट्रेड यूनियनों, तथा किसानों, खेत मजदूरों, महिलाओं, छात्रों, युवाओं, एवं अन्य व्यसवसायिक मजदूरों को इन नीतियों के विरोध में जन संगठनों के मंच के आह्वान पर भारी प्रतिरोध करने के लिये हार्दिक बधाई दी गई। डंकल प्रस्तव के विरोध में 3-9 दिसम्बर तक विरोध कार्रवाईयां करने के लिये भी उन्हें बधाई दी गई। एइस्को के निजीकरण के विरोध में जबरदस्त संयुक्त हड़ताल कराने के लिये इकट्ठा होने पर इस्पात उद्योग में सक्रिय मजदूरों और ट्रेड यूनियनों जिनमें इंटक तथा बी एम एस भी शामिल है, को बधाई दी गई। उन मजदूरों और ट्रेड यूनियनों को भी बधाई दी गई जिन्होंने उर्वरक, कोयला, कपड़ा, सड़क परिवहन, तेल इत्यादि उद्योगों एवं वित्तीय क्षेत्र में इन नीतियों के विरोध में संयुक्त संघर्ष करने के प्रयास किये हैं। बैठक में सभी ट्रेड यूनियनों एवं मजदूरों को आह्वान किया गया कि वे इन संघर्षों के द्वारा हुई एकता को मजबूत करें, ठोस कार्रवाई योजनाओं के द्वारा अपना आंदोलन तेज करें और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में साधारण जनता को इन आंदोलनों के लिये लामबंद करें।

बैठक में सभी संगठनों को आह्वान किया गया कि वे संयुक्त रुप या स्वतंत्र रुप से जत्थे संगठित करें जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर राज्यों की राजधानियों और राज्यों की राजधानियों से वे देशव्यापी जत्थों का रुप लेकर देश की राजधानी नयी दिल्ली में पहुंचें जहां उनकी चरम परिणिति संसद के समक्ष एक जनसत्ता के रूप में होगी। यह कार्रवाई यथाशीघ्र शरू कर देनी चाहिये। बैठक में जन संगठनों के राष्ट्रीय मंच से अपील की गई कि वह आंदोलन के अगले चरण के अनुरूप कार्रवाई योजना को कार्यरूम दे।